

किसान फायदा उठा सकें और अपनी फसलों के लिये बो सकें ।

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो इस का प्रचार कुछ सीमित है क्योंकि हमारे पास अभी इतना बीज पैदा नहीं हुआ कि हम सब किसानों को दे सकें । मगर जहाँ जहाँ पैदा हो सका है, कोशिश की जा रही है कि उसका जल्दी बढ़ाया जाय ।

श्री नवाब सिंह चौहान : मेरा मतलब बीज का मल्टीप्लिकेशन और बढ़ाने से नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपने मक्के के बीज की नस्ल को सुधारने का कोई ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे बड़े पैमाने पर वह किसानों को दिया जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : बड़े ही पैमाने पर इस बीज को पैदा कर रहे हैं । यह एक खाम बीज हम पैदा कर रहे हैं । जितना वह पैदा होगा उतना ही हम किसानों को दे सकते हैं उससे ज्यादा नहीं ।

डा० रघुनाथ प्रसाद दुबे : उनका सवाल यह है कि आप उसे एक्सपैरीमेंटल फार्म में गो कर रहे हैं या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसकी देखभाल के लिये काफी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता रहती है । चारों सेक्टरों में इसका प्रोडक्शन हो रहा है ।

SHRI M. VALIULLA: How long this experiment has been going on?

Mr. CHAIRMAN: Mr. Jain will answer for all of them.

श्री ए० पी० जैन : यह दो-नसली मक्का को पैदा करने का जो काम है वह काफी कठिन है और इसमें काफी वक्त लगता है क्योंकि पहले दो बीजों को क्रस किया जाता है और फिर उसके बाद भी क्रस किया जाता है । पहले रिसर्च होती है और उसके बाद में जब रिसर्च कामयाब हो जाती है, उनमें से जो अच्छे बीज होते हैं वे एक्सपैरीमेंटल फार्म में पहुँचा

दिये जाते हैं । वहाँ एक दो साल के बाद बीज किसानों को दिया जाता है ।

श्री नवाब सिंह चौहान : मैं यह पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके एक्सपैरीमेंट हो रहे हैं काश्मीर में और कई जगहों में, तो वहाँ क्या कोई ऐसा स्ट्रेन निकला है क्रॉसिंग करने के बाद, जिसको कि ठीक ढंग से किसान इस्तेमाल कर सकें ? अगर निकला है तो उससे क्या और कितना फायदा हुआ है ?

श्री ए० पी० जैन : मैंने आपसे कहा, इसमें कुछ समय लगता है । अभी तो एक साल की स्कीम है और हाइब्रिड स्ट्रेन निकालने में दो दो, तीन तीन वर्ष लग जाते हैं ।

श्री किशोरी राम : किसानों को यह बीज किस बेमिस पर दिया जाता है ?

(कोई जवाब नहीं मिला)

श्री ए० बी० कुन्हम्बु : इस बीज को उपजाने में कितने किसान इसमें पड़ते हैं, क्या इसके बारे में कह सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : काफी किसान हैं । 25,000 lbs. seed will be evolved and it will be distributed. 25,000 lbs. will be produced in the Terai area of U.P. and 17,500 lbs. will be produced in the Gokak Canal area of former Bombay State. It will be given to a large number of farmers. It has been distributed to a large number in Punjab.

देहली मिल्क सप्लाय स्कीम

*३६७. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के १९५६-५७ के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ २६ पर पैरा ६१ को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहली मिल्क सप्लाय स्कीम के लिये कोलम्बो योजना के अन्तर्गत न्यूजीलैंड

सरकार जो प्लांट देने को है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; इस प्लांट में क्या मशीनरी होगी और अनुमानतः उसका क्या मूल्य होगा;

(ख) यह प्लांट और डेरी किस स्थान पर स्थापित होंगे और दो हजार दुधारू पशु किस स्थान पर रखे जायेंगे ;

(ग) कितना दूध डेरी के पशुओं से प्राप्त किया जायेगा और कितना दूध बाहर से एकत्रित किया जायेगा; और

(घ) डेरी में कितना (१) होल मिल्क और कितना (२) टोन्ड मिल्क तैयार होगा ?

†[DELHI MILK SUPPLY SCHEME

*367. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to refer to paragraph 6.1 on page 26 of the Annual Report of the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture) for 1956-57 and state:

(a) the steps being taken by Government in regard to the plant which is expected to be provided by New Zealand Government under the Colombo Plan for the Delhi Milk Supply Scheme; what machinery the plant will consist of and what will be its estimated cost;

(b) the name of the place where the plant and the dairy will be located and the place where the two thousand milch cattle will be kept;

(c) the quantity of milk proposed to be secured from the cattle of the dairy and the quantity of milk that will be collected from outside; and

(d) the quantity of (i) whole milk and (ii) toned milk expected to be prepared at the dairy?]

कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्ण-
रत्न) : (क) से (घ) तक सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) न्यूजीलैंड से कोई प्लांट प्राप्त नहीं होना है । लेकिन कोलम्बो योजना के अधीन दिल्ली दूध योजना को न्यूजीलैंड सरकार ने सहायता के रूप में ८,००,००० पाँड देना स्वीकार किया है । यह रकम केन्द्रीय डेरी और उससे सम्बन्धित ग्रामीण दूध इकट्ठा करने और टन्ड करने के केन्द्रों के लिये आयात किये जाने वाले मिल्क प्रोसेसिंग (milk processing) सामग्री के मूल्यों को देने के लिये इस्तेमाल की जायेंगी । इस सामग्री का मूल्य अनुमानतः १५३ लाख रुपये है ।

(ख) केन्द्रीय डेरी, जिसमें मुख्य प्लांट लगेगा, दिल्ली में पश्चिम पटेलनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थापित की जायेगी । दिल्ली से हटाये जाने वाले दुधारू पशुओं को बादली के पास एक ढोर कालौनी में रखा जायेगा ।

(ग) ढोर कालौनी से लगभग ३५० मन और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से ६६५० मन ।

(घ) मात्राओं के बारे में अनुमान लगाना अभी कठिन है । शुरू में केवल होल मिल्क बेचा जायेगा, लेकिन यदि मांग हुई तो टोन्ड मिल्क भी तैयार किया जायेगा ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI M. V. KRISHNAPPA): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) No plant is to be received from New Zealand. But the New Zealand Government has agreed to make a grant-in-aid of £ 800,000, to the Delhi Milk Scheme under the Colombo Plan. The amount will be utilised for meeting the cost of imported milk-processing equipment required for the Central Dairy and its ancillary rural milk collection and chilling centres. The cost of equipment is estimated at Rs. 153 lakhs.

(b) The Central Dairy, which will house the main plant, will be located

in Delhi near the West Patel Nagar Railway Station. The milch animals, removed from Delhi, will be housed at a cattle colony near Badli.

(c) About 350 mds, from the cattle colony and 6,650 mds. from the other rural areas.

(d) It is difficult, at this stage, to work out the quantities. Only whole milk will be sold in the beginning, but toned milk will be prepared, if there is a demand for it.]

श्री नवाब सिंह चौहान : यह सामान लेने के लिये जो ८ लाख पौंड की सहायता न्यूजीलैंड सरकार की ओर से दी गई है, तो क्या आपने डेरी का सामान मंगाने का आर्डर दे दिया है ? अगर दे दिया है तो किस देश को, और उस सामान के आने में क्या देर है ?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : अभी दिया नहीं है । १९५८ में वह दिया जाने वाला है ।

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या मशीन को मंगाने के लिये आर्डर देने के संबंध में किसी और देश से भी बातचीत हुई है ?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : अभी नहीं । The scheme is on hand. The work is likely to commence from next February.

DR. R. P. DUBE: From which country are you getting the machinery?

SHRI M. V. KRISHNAPPA: We have not yet drawn the finance and the personnel. The question refers only to New Zealand. Under the New Zealand aid proposal, they have promised to give £800,000 and we will make use of it for importing machinery when we require it.

श्री नवाब सिंह चौहान : यह जो विवरण है इसके "ख" हिस्से में बतलाया गया है कि डेरी पटेलनगर रेलवे स्टेशन के पास बनायी जायेगी और दिल्ली के जो मवेशी हैं उनको वहां पर भेजा जायेगा । तो स्कीम में दिल्ली के मवेशियों को वहां पर रखने का क्या इंतजाम रखा गया है ?

श्री एम० बी० कृष्णप्पा : पटेलनगर के पास जो डेरी होगी वह ज्यादा बड़ी होगी । चिलिंग और मिल्क क्लेक्टिंग सेन्टर दूसरी जगह में होगा ।

श्री नवाब सिंह चौहान : इस विवरण में बतलाया गया है कि ३५० मन प्रति दिन तो यहा से इकट्ठा होगा और ६,६५० मन बाहर से लाया जायेगा । तो क्या कारण है कि बाहर से दूध आया ?

डा० पी० एम० देशमुख : अभी हमारी जो स्कीम है वह बहुत ही अर्ली स्टेज के अन्दर है । अभी तो इसकी शुरुआत हो रही है। यह ७ लाख मन की जो बातचीत हो रही है तो यह बहुत अर्से के बाद होगी । अभी दूध को पैदा करने और बाहर से खरीदने, दोनों के बारे में बात हो रही है ।

श्री नवाब सिंह चौहान : आपने जो यह स्कीम मंजूर की है, इसमें जो यह होल मिल्क और टोन्ड मिल्क लिखा हुआ है, इसके क्या मानी है ?

श्री ए० पी० जैन : होल मिल्क के मानी है शुद्ध दूध के और टोन्ड मिल्क के मानी यह है कि स्किम्ड मिल्क का जो पाऊंडर बनता है उसको करीब करीब आधा तादाद में होल मिल्क के साथ मिलाया जाता है। उसका जो दूध बनता है वह टोन्ड मिल्क कहलाता है ।

SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM: May I know, Sir, if the Government has received some complaints from the farmers whose land has been taken for making the dairy that proper compensation has not been paid to them?

SHRI A. P. JAIN: The question of payment of compensation does not arise as yet, because we are just taking over the land. Of course, the farmers do not like that their land should be taken over, but when it becomes necessary in the public interest it has to be taken over.

DR. P. C. MITRA: May I know, Sir, whether the rate has also been fixed

for the retail sale of whole milk, so that every poor man in the country can buy that?

SHRI M. V. KRISHNAPPA: No detail has been worked out.

SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM: May I know, Sir, if they have given some alternative suggestions about some other land which is not used for the cultivation and what Government is considering about that suggestion?

SHRI A. P. JAIN: We have considered all the possible sites that could be acquired and this is the only site which has been found to be useful.

*368. [*The questioner (Shri N. R. Malkani) was absent. For answer, vide col. 2707-2708 infra.*]

DANGER TO PUBLIC HEALTH AROUND KARBALA REFUGEE COLONY

*369. **SHRI MAHESWAR NAIK:** Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several blocks of houses intended for occupation by displaced persons at Karbala have been turned into cattle pounds and godowns for storing fodder by dairy farmers; and

(b) if so, the steps taken by Government in this connection?

THE MINISTER OF HEALTH (SHRI D. P. KARMARKAR): (a) and (b). It is understood that about 300 unlicensed cattle are kept in the old monuments near Karbala by displaced persons and that some of these persons have unauthorisedly occupied a few ground floor tenements and are also using them as fodder godowns. Removal of unauthorised dairies is possible only after alternative sites could be found for construction of cattle byres as well as residences for the 'Gwalas'. This matter is under examination.

I should like to add that these houses which are being used for fodder

are under the control of the Ministry of Rehabilitation, who will no doubt take appropriate action.

SHRI M. VALIULLA: Is it the policy of the Government that even though they are unauthorised occupants, Government will look for alternative places and then only they will be vacated from these houses?

SHRI D. P. KARMARKAR: The cattle have come there and they have been staying there for some time. Now, unless we are able to make good arrangements for them, it is difficult to remove them from there, because they have to be somewhere and, therefore, it is that it might take time. The Delhi Milk Supply scheme contemplates *inter alia* to remove unauthorised dairies from the city, but it might take about two or three years' time before the scheme is fully implemented. And, therefore, it was thought necessary to make temporary arrangements for shifting cattle.

SHRI MAHESWAR NAIK: May I know the number of tenements which have been constructed and are lying unoccupied; and, why are they so lying unoccupied?

SHRI D. P. KARMARKAR: 'The number of tenements constructed lying unoccupied'—I and the W.H.S. Ministry will require notice.

SHRI M. VALIULLA: The flats were intended for occupation long ago. How many blocks are lying unoccupied?

SHRI D. P. KARMARKAR: We have no information about this. Regarding any other information on this point, I should like to have notice.

TRAMWAY SYSTEM IN DELHI

*370. **SHRI MAHESWAR NAIK:** Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the present number of tram cars plying in Delhi; and